CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEASI TIMES
हिन्दी

सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR
DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for
Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for
Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

@ceasi_india

CEASI TIMES

ओडिशा के कृषि निर्यात क्षमता को बढ़ावा

भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने ओडिशा सरकार के सहयोग से 25 अप्रैल 2025 को भुवनेश्वर स्थित OUAT में एक कार्यशाला सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 10 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जिनमें किसान उत्पादक संगठन (FPOs), महिला कृषि उद्यमी, निर्यातक और सरकारी विभागों ने भाग लिया। प्रदर्शित उत्पादों में कोरापुट का काला जीरा चावल, नयागढ़ का कांतेमुंडी बैंगन, कंधमाल हल्दी पाउडर और सालेपुर रसगुल्ला शामिल थे, जो ओडिशा की कृषि विविधता और निर्यात क्षमता को दर्शाते हैं।कार्यशाला में जैविक खेती पर संशोधित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन नीति (NPOP) के दिशा-निर्देशों के तहत तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इसके साथ ही चावल के निर्यात रणनीतियों और GI टैग प्राप्त उत्पादों में मूल्य संवर्धन पर भी चर्चा की गई। चर्चा में प्रमाणन प्रक्रिया, ढांचागत विकास और निर्यात लॉजिस्टिक्स को भी प्रमुखता दी गई।

एक विशेष सत्र में 30 से अधिक जैविक उत्पादक समूहों और प्रमाणन संस्थाओं को एक मंच पर लाया गया, जिससे सहयोग और ज्ञान-साझा को बढ़ावा मिला। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ओडिशा के कृषि निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और मूल्य श्रृंखला में जुड़े सभी हितधारकों को एकजुट करना था।

विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2025: पशु स्वास्थ्य और टीमवर्क पर जोर

विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 के अवसर पर पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पशु चिकित्सकों की भारत की पशुधन-आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिका को सराहा गया, जो 536 मिलियन से अधिक पशुधन की देखभाल और फुट एंड माउथ डिज़ीज़ (FMD) जैसी बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

वक्ताओं ने देशी नस्लों के महत्व, इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) जैसी तकनीकों और 'भारत पशुधन' जैसे डिजिटल टूल्स द्वारा पशु स्वास्थ्य की निगरानी पर प्रकाश डाला। 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण को मानव और पशु स्वास्थ्य के बीच संबंधों के बेहतर प्रबंधन के लिए उपयोगी बताया गया।कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और 3,000 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन सहभागिता की, जिनमें छात्र, शोधकर्ता और किसान शामिल थे। इस कार्यशाला ने मजबूत पशु चिकित्सा ढांचे और कौशल विकास की आवश्यकता को दोहराया, जिससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका सशक्त हो सके।

"पशु स्वास्थ्य एक टीम का काम है" इस वर्ष की थीम रही, जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। तकनीकी सत्रों में रोग निगरानी, जूनोटिक (जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले) रोगों की रोकथाम और FMD नियंत्रण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

CEASI TIMES

किसानों को जानकारी देने के लिए मुक्तसर में शुरू हुआ यूट्यूब चैनल

मुक्तसर के कृषि विभाग ने "मुक्तसर खेती सूचनावां" नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, ताकि किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी आसान और सुलभ तरीके से समय पर मिल सके। इस पहल का उद्देश्य था कि किसानों को जरूरी जानकारी पाने के लिए बार-बार कृषि दफ्तर न जाना पड़े और उन्हें समय रहते जानकारी मिल सके।इस चैनल पर मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाएं, आधुनिक खेती के तरीके, उपलब्ध सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाएं जैसे विषयों पर छोटे और सरल वीडियो अपलोड किए जाने की योजना बनाई गई।अधिकारियों ने बताया कि इस चैनल का उद्देश्य किसानों को सही जानकारी देकर उन्हें बेहतर फैसले लेने में मदद करना और उनकी खेती की तकनीकों को सुधारना था।

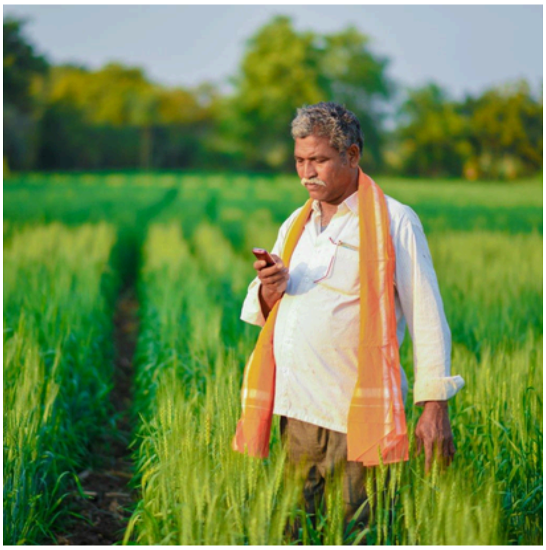

इस चैनल का औपचारिक उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर अभिजीत कपलीश ने किया। स्थानीय किसानों ने इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि यह प्लेटफॉर्म उन्हें और बेहतर जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधा से उन्हें योजनाओं और नई तकनीकों का लाभ लेने में आसानी होगी और दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।

फसल उत्पादन और नवाचार बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री ने ICAR की रणनीतियों की समीक्षा की

केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में ICAR अधिकारियों के साथ चर्चा की, जिसमें चल रहे शोध कार्यों की समीक्षा और भविष्य की रणनीतियों पर बात की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि नवाचार और उत्पादकता को बढ़ाना था। इसमें यह तय किया गया कि रिसर्च और आधुनिक तकनीकों की मदद से सरकारी कृषि योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा।मुख्य चर्चाएं दालें, तिलहन, कपास और मोटे अनाज जैसी फसलों की उपज बढ़ाने पर केंद्रित थीं, जिसमें बेहतर बीज किस्मों और वैज्ञानिक खेती के तरीकों जैसे मृदा परीक्षण और कीटनाशक के सही उपयोग पर ज़ोर दिया गया। किसान विज्ञान केंद्रों (KVKs) की भूमिका को मजबूत करने और महिला व युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में जलवायु के अनुसार अनुकूल खेती को बढ़ावा देने, छोटे किसानों के लिए मॉडल फार्म विकसित करने और प्राकृतिक खेती के प्रमाणीकरण जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। ICAR के वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने भी बैठक में भाग लेकर टिकाऊ और समावेशी कृषि विकास के लिए साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

CEASI TIMES

ओडिशा सरकार ने किसानों को ₹1025 करोड़ ट्रांसफर किए, ₹1 लाख करोड़ की सिंचाई योजना की घोषणा

अक्षय तृतीया और किसान दिवस के अवसर पर, ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत 51 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ₹1025 करोड़ की राशि जमा की। इस सहायता से छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन परिवार, जनजातीय किसान और पहली बार शहरी किसानों को 2025 की फसल की तैयारी में मदद मिली।

भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सरकार ने किसानों की भूमिका को सराहा और उन्हें ओडिशा को अन्न सरप्लस राज्य बनाने में मुख्य भागीदार बताया। साथ ही, बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए जलवायु अनुकूल कृषि अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया ताकि उत्पादन में निरंतरता बनी रहे।

भविष्य की योजनाओं में 15 लाख हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई सुविधा का विस्तार और अगले पांच वर्षों में हर उपखंड में कोल्ड स्टोरेज केंद्र स्थापित करना शामिल है, जिससे फसल के भंडारण और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹3100 प्रति क्विंटल तय किया है, जिससे किसानों को उचित लाभ मिले और कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो।

बिहार सरकार ने अप्रैल तूफानों से प्रभावित किसानों के लिए ₹8.39 करोड़ मुआवज़े की घोषणा की

बिहार सरकार ने अप्रैल की शुरुआत में हुई असमय बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए ₹8.39 करोड़ से अधिक के मुआवज़े को मंज़ूरी दी है। यह राहत आठ ज़िलों—सुपौल, नालंदा, समस्तीपुर, गया, मधुबनी, नवादा, मधेपुरा और बेगूसराय—के गंभीर रूप से प्रभावित किसानों को दी जाएगी। यह सहायता कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत दी जा रही है, जिसका लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी फसल का नुकसान 33% से अधिक रहा है और जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारियों ने दी है।

मुआवज़े की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के ज़रिए सीधे भेजी जाएगी। 9 से 14 अप्रैल के बीच हुए खराब मौसम के दौरान गेहूं, मक्का, दालें, तिल, मूंगफली, प्याज, केला और पान जैसे फसलों को नुकसान हुआ, जिनमें से कुछ फसलें पक चुकी थीं और कुछ कटाई के लिए तैयार थीं।

कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने मिलकर राशि वितरण की व्यवस्था की, जिससे किसानों को समय पर सहायता मिल सके। यह सरकार की किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में मदद करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

CEASI TIMES

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने ऑर्गेनिक खेती में उत्कृष्टता के लिए किसानों को सम्मानित किया

2 मई 2025 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में ऑर्गेनिक खेती में उत्कृष्ट योगदान के लिए तीन किसानों को 'नम्माझवर पुरस्कार' से सम्मानित किया। ये पुरस्कार कोयंबटूर, तिरुप्पुर और नागपट्टिनम जिलों के किसानों को सतत कृषि पद्धतियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिए गए। कोयंबटूर के जी. संपतकुमार को पहला

पुरस्कार मिला, जिसमें ₹2.5 लाख की राशि और एक मेडल शामिल था। तिरुप्पुर के टी. जगदीश और नागपट्टिनम के वी. कालिदास को क्रमशः ₹1.5 लाख और ₹1 लाख की राशि के साथ दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला। इन पुरस्कारों का उद्देश्य राज्य में ऑर्गेनिक खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। तमिलनाडु सरकार राज्य के 386 ब्लॉकों में जागरूकता अभियान और अध्ययन यात्राओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री की 'मन्नुयिर काथु मन्नुयिर काप्पोम' योजना रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देती है, जिससे मिट्टी की सेहत सुधरती है और सुरक्षित भोजन उपलब्ध होता है।

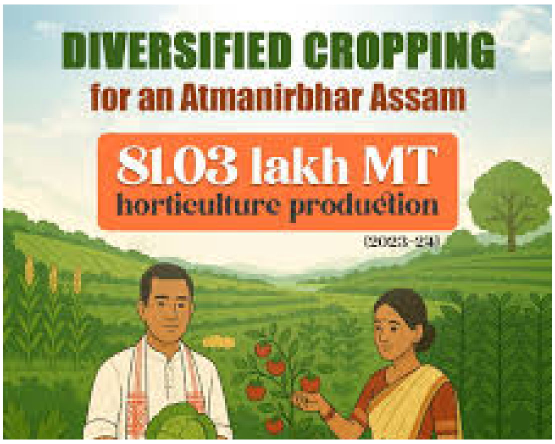

असम में बागवानी से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा,81 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन

2023–24 में असम ने बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिससे राज्य की कृषि प्रणाली में बदलाव देखा गया। इस वर्ष कुल 81.03 लाख मीट्रिक टन बागवानी फसलों का उत्पादन हुआ, जो 6.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया था। ये फसलें कुल फसल क्षेत्र का लगभग 15% हिस्सा थीं, जो यह दर्शाता है कि किसान पारंपरिक धान की खेती से हटकर अन्य फसलों की ओर बढ़ रहे हैं।इस बदलाव के कई कारण थे, जैसे मिट्टी का कटाव , औद्योगिकीकरण और आधारभूत ढांचे के विकास के कारण धान की खेती के लिए भूमि कम होना। किसान अब फल, सब्जियां और मसालों की खेती में अधिक रुचि दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी बाजार में ज्यादा मांग और बेहतर कमाई की संभावना है। नई तकनीक, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, उन्नत कटाई और परिवहन सुविधाओं के उपयोग से उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है।असम से बागवानी उत्पादों का निर्यात भी तेजी से बढ़ा है।राज्य से नींबू लंदन, अनानास दुबई और अदरक-हल्दी स्विट्ज़रलैंड भेजे गए हैं, जो एपीडा से मान्यता प्राप्त निर्यातकों के माध्यम से हुआ। युवा किसान भी बागवानी की लाभकारी संभावनाओं और निर्यात के अवसरों को देखते हुए इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे इस विकास को और गति मिली है।

CEASI TIMES

तटीय राज्यों की मत्स्य बैठक 2025: ₹255 करोड़ की योजनाएं टिकाऊ मछली पालन के लिए घोषित

मुंबई में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह की अगुवाई में आयोजित तटीय राज्यों की मत्स्य बैठक 2025 के दौरान, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत सात तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ₹255 करोड़ की परियोजनाएं घोषित की गईं। इस अवसर पर 5वीं समुद्री मत्स्य गणना और मछुआरों के 12 लाख घरों से डिजिटल डेटा एकत्र करने के लिए विकसित किया गया 'व्यास-नव' मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया।

श्री सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) के तहत मछुआरों को वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से एक्वा बीमा का वितरण भी किया। 'व्यास-नव' ऐप, जिसे ICAR-CMFRI द्वारा विकसित किया गया है, डेटा संग्रहण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और डिजिटल बनाने में मदद करेगा।

5वीं समुद्री मत्स्य गणना दिसंबर 2025 तक पूरी की जाएगी, जिसमें समुद्री मछुआरा परिवारों, ढांचागत सुविधाओं और मछली पकड़ने की गतिविधियों का विस्तृत दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इस दौरान कछुआ बचाव उपकरण (टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस) और नौकाओं में संचार हेतु मानक प्रक्रिया (SOP) से संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी किए गए, जिससे सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सके।

कस्टम हायरिंग योजना से एम.पी. के किसान और ग्रामीण रोजगार को मिला बढ़ावा

शाहडोल, मध्य प्रदेश में किसानों की मदद के लिए कृषि यंत्रों पर 40% तक की सब्सिडी और 3% ब्याज में छूट के साथ कस्टम हायरिंग योजना (SMAM के अंतर्गत) शुरू की गई। इस योजना से छोटे किसान न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा सके, बल्कि कृषि यंत्र किराए पर देकर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित करने लगे।

शाहडोल में 52 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए, जिससे आधुनिक कृषि उपकरणों तक गांवों में आसान पहुंच सुनिश्चित हुई और पिछड़े क्षेत्रों में कृषि कार्यों की दक्षता बढ़ी।

सीमा बैगा और नीरज सिंह परमार जैसे किसानों ने इन यंत्रों का उपयोग करके न केवल अपनी उपज में सुधार किया, बल्कि अतिरिक्त आमदनी भी कमाई। इससे ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा मिला।

इस योजना से 18 से 40 वर्ष के बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को भी लाभ मिला। उन्हें कृषि यंत्रों के संचालन और रख-रखाव का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद वे सब्सिडी पर ये उपकरण खरीद सके।

CEASI TIMES

कर्नाटक में रबर बागानों का डिजिटल मैपिंग प्रोजेक्ट शुरू

रबर बोर्ड ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में रबर बागानों की ज़मीन और सीमाओं को डिजिटल रूप से मैप करने की योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य बागानों के प्रबंधन में सुधार करना है, और इसे अन्य क्षेत्रों में भी फैलाया जाएगा। यह परियोजना यूरोपीय संघ के वनों की कटाई रोकने वाले नियम (EUDR) जैसे वैश्विक स्थिरता मानकों के अनुरूप है।

EUDR के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, रबर बोर्ड ने त्रयंबु टेक सॉल्यूशंस प्रा. लि. के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी सप्लाई चेन की निगरानी और ट्रैसेबिलिटी सिस्टम को विकसित करने में मदद करेगी। इस प्रक्रिया में रबर बागानों की 100% बहुभुज (पॉलीगन) मैपिंग की जाएगी, जिससे सप्लाई चेन में पारदर्शिता और निगरानी बेहतर होगी।

मैपिंग के साथ-साथ, रबर बोर्ड भारतीय स्थायी प्राकृतिक रबर (ISNR) योजना के तहत प्राकृतिक रबर को प्रमाणित करने पर भी कार्य कर रहा है। इससे भारत की रबर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी। सभी एकत्रित आंकड़े एक सुरक्षित और केंद्रीकृत डाटाबेस में संग्रहित किए जाएंगे, जिससे गोपनीयता बनी रहे और जानकारी की सत्यता सुनिश्चित हो सके।

सिक्किम में माइक्रोग्रीन्स खेती को बढ़ावा, आजीविका और शहरी कृषि को मिलेगा बल

सिक्किम कृषि विभाग ने माइक्रोग्रीन्स खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य खेती में विविधता लाना और नई आजीविकाएं सृजित करना है। इस परियोजना में फ्लोरीकल्चर और एग्री-बिजनेस मैनेजमेंट केंद्र (Cofam) ने तकनीकी सहयोग दिया, और 150 सरकारी अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त टैरेस और वर्टिकल फार्मिंग तकनीकों में प्रशिक्षण दिया गया।इस परियोजना का फोकस माइक्रोग्रीन्स को शहरी इलाकों जैसे गंगटोक में एक सतत खेती विकल्प के रूप में पेश करना था, जहां ज़मीन की उपलब्धता कम है। इसमें स्थानीय निवासियों और संस्थानों, खासकर पर्यटन से जुड़े लोगों को अपनी खुद की साग-सब्ज़ी उगाने के लिए प्रेरित किया गया। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी और व्यवसाय के नए अवसर भी मिलेंगे।वर्टिकल फार्मिंग के लिए पॉलीहाउस लगाए गए हैं, जिससे पूरे साल माइक्रोग्रीन्स की खेती संभव हो सके। परियोजना के तहत कृषि अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे यह ज्ञान किसानों और युवाओं तक पहुंचा सकें, जिससे उन्हें कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में नई आमदनी के रास्ते मिलें।

CEASI TIMES

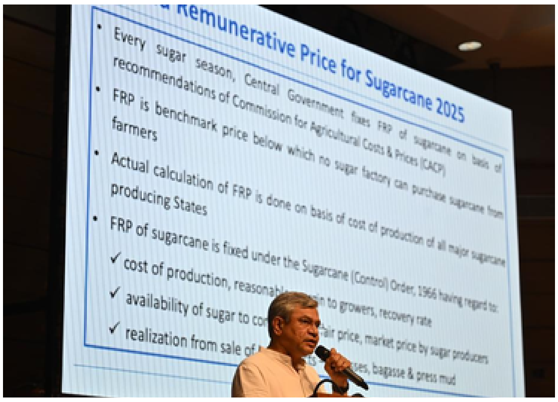

2025–26 सीजन के लिए गन्ने का मूल्य ₹355 प्रति क्विंटल किया गया

2025–26 के शुगर सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) ₹355 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल के ₹340 के मुकाबले 4.41% अधिक है। यह बदलाव किसानों के हितों और शुगर मिलों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके साथ ही गन्ने में चीनी की रिकवरी दर के आधार पर दाम में बदलाव की व्यवस्था भी की गई है, जिससे सभी को न्यायसंगत लाभ मिले।

किसानों को और सहयोग देने के लिए यह भी तय किया गया है कि जिन मिलों में रिकवरी दर 9.5% से कम है, वहां किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। ऐसे मामलों में किसानों को ₹329.05 प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। संशोधित FRP ₹173 की उत्पादन लागत से 105.2% अधिक है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिल सकेगा।

गन्ना खेती और इससे जुड़ी उद्योगों से देशभर में लगभग पांच करोड़ किसान और पांच लाख मिल कर्मचारियों की आजीविका जुड़ी हुई है। इस मूल्य निर्धारण का निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों और विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।

भारत ने उपज बढ़ाने के लिए जीनोम-संपादित धान की किस्में लॉन्च कीं

भारत ने दो नई जीनोम-संपादित धान की किस्में—कमला (DRR धान-100) और पुसा DST राइस 1—जारी की हैं, जो 30% तक ज्यादा उपज देने के लिए विकसित की गई हैं। ये किस्में पारंपरिक धान की तुलना में 15–20 दिन पहले पकती हैं और पानी की खपत के साथ ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम करती हैं। इससे किसानों को उपज और पर्यावरण—दोनों में लाभ होगा।

फील्ड ट्रायल में कमला किस्म ने सांबा मसूरी से 19% ज्यादा उपज दी, जबकि पुसा DST राइस 1 ने मिट्टी के प्रकार के अनुसार 9–30% तक अधिक उत्पादन दिखाया। इन किस्मों की सिफारिश दक्षिण, पूर्व और मध्य भारत के कई राज्यों के लिए की गई है।

ये बीज किसानों तक पहुंचने में कुछ साल लग सकते हैं, क्योंकि इन्हें प्रमाणित बीज उत्पादन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन यह शुरुआत भारत में टिकाऊ और उच्च उत्पादकता वाली खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

कमला और पुसा DST राइस 1 जैसी उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों से विकसित किस्में भारत के कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करेंगी।

CEASI एक्टिविटीज

अयोध्या में सतत गन्ना खेती को बढ़ावा

सश्वत मिठास परियोजना के तहत, एग्रीकल्चर स्किल्स इंडिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और UPL SAS लिमिटेड मिलकर अयोध्या में सतत गन्ना खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को पर्यावरण के अनुकूल खेती की जानकारी और तकनीक सिखाना है। इसके लिए एक टीम खेतों का सर्वे कर रही है ताकि वर्तमान खेती के तरीकों को समझा जा सके और सुधार की संभावनाएं पता चल सकें।

इस परियोजना के तहत बनाए गए प्रदर्शन प्लॉट (डेमो प्लॉट) पर गन्ना खेती के टिकाऊ तरीके जैसे पानी का सही उपयोग, मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाना और जैविक खादों का उपयोग दिखाया जा रहा है। इन तरीकों के माध्यम से किसानों को अधिक उपज और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

परियोजना का उद्देश्य किसानों को यह समझाना है कि टिकाऊ खेती से न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इसके तहत अयोध्या में 1 एकड़ भूमि पर 10 मॉडल प्लॉट तैयार किए गए हैं जो किसानों को सही तरीका दिखाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।

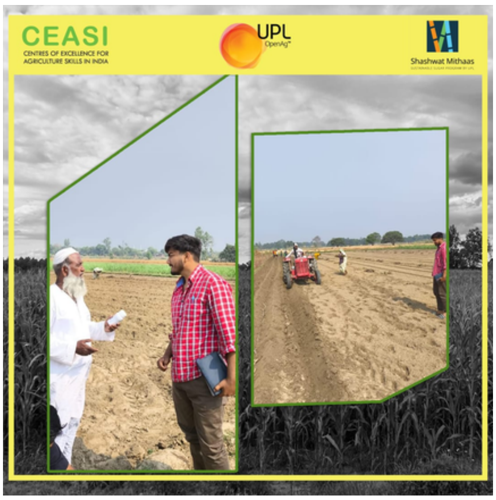

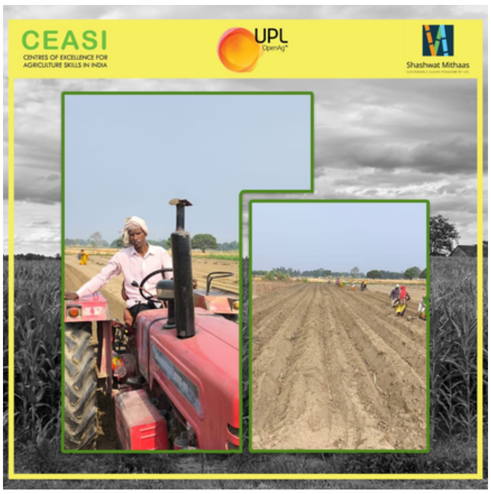

CEASI एक्टिविटीज

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI) ने खानापारा, असम में डेयरी पशु चारे पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI) ने खानापारा, असम में एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य डेयरी किसानों, विस्तार कार्यकर्ताओं और संबंधित लोगों को आधुनिक पशु चारे की तकनीकों के बारे में जानकारी देना था, जिससे दूध उत्पादन और पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

इस कार्यक्रम में डेयरी किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में वैज्ञानिक डेयरी पद्धतियों को अपनाने की गहरी रुचि है। CEDSI की यह पहल उत्तर-पूर्व भारत में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और सर्वोत्तम तरीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है।

इस सत्र का संचालन डेयरी क्षेत्र के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ ने किया, जिन्होंने संतुलित पोषण, चारे की योजना, चारा प्रबंधन और किफायती खिलाने की तकनीकों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। प्रतिभागियों को वैज्ञानिक तरीकों से चारा देने के व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी गई, जिससे पशु उत्पादकता बढ़ाई जा सके और डेयरी व्यवसाय अधिक लाभदायक और टिकाऊ बन सके।

हम कौन हैं

"सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स (CEASI)" एक स्वायत्त संगठन है, जो "एग्रीकल्चर स्किल कौंसिल ऑफ़ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य करता है। ASCI, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत काम करता है और इसका उद्देश्य किसानों, श्रमिकों, स्व-रोज़गार करने वाले पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण करना है। यह कार्यक्रम कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए तैयार किया गया है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों का एक शीर्ष संगठन है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेचानिज़शन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India